बिहार की ई-शक्ति पर नीलेकणि फिदा

कहा, देशभर में यूआईडी के इस्तेमाल के लिए रोल मॉडल बन सकती है यह योजना

हरिकिशन शर्मा

नई दिल्ली

मनरेगा, पीडीएस जैसी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यूआईडी के इस्तेमाल की तैयारी कर रही केंद्र सरकार बिहार की एक योजना को पूरे देश के लिए रोल मॉडल मान रही है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने मंगलवार को राज्य की 'ई-शक्ति' योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि देशभर में सरकारी कार्यक्रमों के साथ 'आधार' के तालमेल के लिए इसे रोल मॉडल बनना चाहिए।

वित्त मंत्रालय ने केरोसिन और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को यूआईडी आधारित प्रणाली पर सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का उपाय तलाशने को सोमवार को ही नीलेकणि की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स गठित किया है।

नीलेकणि ने यह बात राज्य की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई बैठक के दौरान कही।

बैठक के बाद नीतीश ने बताया कि बिहार की ई-शक्ति फिलहाल पायलट योजना के आधार पर पटना जिले में चल रही है। इसके तहत मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी से लेकर मस्टर रोल, भुगतान और कार्य का ब्यौरा सब कुछ ऑनलाइन

ई-शक्ति की शक्ति

■ ई -शक्ति के के तहत मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी से लेकर मस्टर रोल भुगतान और कार्य का ब्यौरा सब कुछ ऑनलाइन व बायोमेट्रिक्स से

तथा बायोमीट्रिक्स यानी अंगुलियों की छाप के जरिये ही होता है। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। नीलेकणि मनरेगा में यूआईडी के क्रियान्वयन के लिए अब ई-शक्ति को मॉडल बनाकर बाकी योजनाओं में भी ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं।

नीतीश ने केंद्र से फ्लैगशिप कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बंद करने की मांग की है। उन्होंने यह मांग वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के समक्ष उठायी।

उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्र की कई सौ योजनाएं चल रही हैं। इनके दिशा निर्देश दिल्ली में बैठकर तय होते हैं, जो एक -दूसरे राज्य के हिसाब से फिट नहीं बैठते। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी केंद्रीय योजनाओं की संख्या घटाने की सिफारिश की थी। इसलिए सिर्फ फ्लैगशिप कार्यक्रमों को छोड़ बाकी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए।